



परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे ↓

परीक्षा का विषय	विषय कोड	परीक्षा का माध्यम
राजनीति विज्ञान	L 3 0	हिन्दी
स्टीकर तौर के निशान ↓ से मिलकर बनाये		
परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे उत्तर पुस्तिका का क्रमांक 320- 1236950		
अंकों में परीक्षार्थी का रोल नम्बर		
<input checked="" type="checkbox"/> 2 0 3 2 4 6 7 0 0		
शब्दों में		
<input checked="" type="checkbox"/> दो शून्य तीन दो चार छः सात शून्य शून्य		

प्रश्न क्रमांक	केवल परीक्षक द्वारा भरा जावे	प्रश्न	समस्त प्रश्नों के	पूट	क्रमिक	क्रमिक
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
कुल प्राप्त/क शब्दों में						

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे

कन्द्राध्यक्ष/सहायक कन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षक द्वारा भरा जावे

परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे

क - पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या अंकों में शब्दों में

ख - परीक्षार्थी का कक्ष क्रमांक

ग - परीक्षा का दिनांक

परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केंद्र के नामों की मुद्रा

हा० से० सर्टि० परीक्षा केन्द्र क्रमांक-222254

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

कन्द्राध्यक्ष/सहायक कन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर

संयोजिता सिंह

[Signature]

परीक्षक एवं उपमुख्य परीक्षक द्वारा भरा जावे ↓

प्रमाणित किया जाता है कि मूल्यांकन के समय पूरक उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या उपरोक्तानुसार सही पाई होले क्राफ्ट स्टिकर क्षतिग्रस्त नहीं पाया गया तथा अन्दर के पृष्ठों के अनुरूप मुख्य पृष्ठ पर अंकों की प्रविष्टी एवं अंकों का योग सही है।

निर्धारित मुद्रा : नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, परीक्षक क्रमांक एवं पदांकित संस्था के नाम की मुद्रा लगाए।

उप मुख्य परीक्षक के हस्ताक्षर

GEX S. Balaghat
V.NO. - 782769

G.K. PATIL (V.A.)
G.H.S.S MATE
V.NO. - 782782

नोट :- "हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल वाणिज्य संकाय के विषयों तथा हाईस्कूल परीक्षा में प्रायोगिक विषय को छोड़कर शेष विषयों हेतु नियमित एवं स्वाध्यायी छात्रों के लिये प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा किन्तु नियमित छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक का 80% अधिमान एवं स्वाध्यायी छात्रों को 100 अंकों के प्राप्तांक ही अंकसूची में प्रदर्शित किये जायें।"

[Signature]
R.K. CHOURE (Lect.)
G.H.S.S. Mendki
V.No.-782756

Laser/Inkjet/Copier Label A4ST-16

99.1x33.9mmx16



2

पृष्ठ 2 क अन्त



प्रश्न क्र.

प्रश्न क्रमांक (1)

उत्तर : →
सही विकल्प : →

(i) (स) 562

(ii) (स) सन 1985

(iii) (अ) भारत - पाकिस्तान

(iv) (स) नीली

(v) (अ) विश्व का मण्डलीकरण

**B
S
E**

प्रश्न क्रमांक (2)

उत्तर :
रिक्त स्थानों की पूर्ति : →

(i) राष्ट्रध्वज ।

(ii) सन 1954 ।

(iii) 24 अक्टूबर ।

R.K. ROY
G.D. SINGH
V.No-18513



(iv) परिवर्तन ।

(v) निरक्षरता ।

प्र० क्रमांक (3)

उत्तर :- एक वाक्य में उत्तर ! →

(i) मौलिक सदस्य ।

(ii) 'सार्क' ।

(iii) सुरक्षा परिषद ।

(iv) वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन के नाम से जाना जाता है ।

(v) P.W.G का पूरा नाम ! →

"Peoples War Group" है ।



प्रश्न क्र.

प्र० प्रश्न (८)

उत्तर :-

सत्य / असत्य :- →

- (i) असत्य ✓
- (ii) सत्य ✓
- (iii) सत्य ✓
- (iv) सत्य ✓
- (v) सत्य ✓

**B
S
E**

Inkjet/Copier Label A4ST-16 897

प्र० क्रमांक (९)

सही जोड़ी :-

(अ)

(ब)

- | | | | |
|-------|-------------------------------|---|------------------|
| (i) | बी. एन. रज | - | सर्वैधानिक रक्षा |
| (ii) | सर्वेण्ट्स ऑफ इण्डियन सोसायटी | - | पूणे |
| (iii) | बालिका समृद्धि योजना | - | 1997 |
| | गोरखा लैण्ड आन्दोलन | - | असम |
| | प्रमाण्डु अप्रसार संधि | - | 1968 |



प्रश्न क्र.

प्र० क्रमांक (6)

उत्तर : →

जम्मू कश्मीर का 32,000 हजार वर्ग मील का वह क्षेत्र जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, पाकिस्तान उसी को आजाद कश्मीर अथवा 'पाक-अधिकृत कश्मीर' कहता है।

91X111116'888

**B
S
E**

प्र० क्रमांक (7)

(अथवा)

उत्तर : →

भारत ने अपनी पहली सैन्य टुकड़ी 27 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से कश्मीर भेजी।

प्र० क्रमांक (8)

उत्तर : →

सविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जी० वी० रव शर्मा थे।

प० क्रमांक (9)

उत्तर : → (अथवा)

चुटनिरपेक्षता का अर्थ : →
 चुटनिरपेक्षता का आशय है शीत युद्ध के परिप्रेक्ष्य में दोनों गुटों से सामान धूसी बनाये रखने की नीति " "

इसे निर्दिष्ट स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया गया है।

प० क्रमांक (10)

उत्तर : →
 शिमला समझौते के दो प्रावधान : →

(i) द्विपक्षीय विवाद में किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

(ii) कश्मीर प्रकरण का किसी भी क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जायेगा।

प्र० क्रमांक (11)

(अथवा)

उत्तर : ✍

संविधान निर्माण की तीन आवश्यकताएँ निम्नलिखित हैं : ✍

**B
S
E**

(i) सरकार के मनमाने पूर्ण व्यवहार के प्रति मनुष्य को संरक्षण : ✍

संविधान निश्चित नियमों को संग्रह होता है, जिसका पालन करना सरकार और जनमानस दोनों के लिए आवश्यक होता है।

(ii) सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण : ✍

ऐसा माना जाता है की जनहितकारी शासन के लिए सरकार को कभी भी निरंकुश शक्तियाँ नहीं दी जानी चाहिए।

(iii) राजनीति व्यवस्था के विधि सम्मत प्रगति की गारंटी : ✍

संविधान ही यह सुनिश्चित करता है की राजनीति व्यवस्था का किस प्रकार व्यवस्थित करना है।

प्र० क्रमांक (12)

(अथवा)

उत्तर : →
नागरिकों के तीन मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं : →

B
S
E

(i) अनु० 14 से 18 तक
समानता का अधिकार ।

(ii) अनु० 18 से 22 तक
स्वतंत्रता का अधिकार ।

(iii) अनुच्छेद - 23 से 24 तक
शांति के विरुद्ध अधिकार ।

(iv) अनुच्छेद - 25 से 28 तक
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ।

अनुच्छेद - 29 से 31 तक ।

सांस्कृतिक और शिक्षा विषयक सम्बन्धी
अधिकार ।

प्र० क्रमांक (13)

उत्तर ! →

संयुक्त राष्ट्र संघ के डोई तीन प्रमुख निम्नलिखित हैं ! →

- B
S
E**
- (i) औने वाली विदियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना ।
 - (ii) मूलभूत मानवाधिकारों और कार्य तथा ख स्त्री पुरुष एवं राष्ट्र के मध्य विश्वास को मजबूत करना ।
 - (iii) ऐसी स्थितियों का निर्माण करना जिसमें न्याय तथा संधि एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधिसेम्रोतों से उद्भूत उत्तरदायित्वों का पालन किया जा सके ।
 - (iv) सामाजिक प्रगति तथा जीवन के बेहतर स्तर को बढ़ावा देना ।
 - (v) सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक एवं अन्तर्राष्ट्रीय को प्रोत्साहित एवं पुष्ट करना ।

प्रश्न क्रमांक (14)

उत्तर :-

निः शस्त्रीकरण के मार्ग में आनेवाली प्रमुख बाधाएँ निम्नांकित हैं :-

(i) शस्त्रीकरण में राष्ट्रों का विश्वास :-

**B
S
E**

विश्व का हर राष्ट्र निः शस्त्रीकरण का समर्थक है, परन्तु व्यवहारिक दृष्टिकोण पर हर राष्ट्र को लगता है कि अधिक से अधिक हथियारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है।

(ii) हथियारों के अनुपात पर सहमति न बन पाना :-

निः शस्त्रीकरण की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि बड़े राष्ट्र इस बिन्दु पर सहमति नहीं हो पाते कि विभिन्न राष्ट्रों के पास किस अनुपात में हथियार विद्यमान रहें।

(iii) राष्ट्रों के बीच अविश्वास :-

यदि कोई देश हथियारों का आतंक करता है तो पड़ोसी राष्ट्र यही अनुमान करते हैं कि वह राष्ट्र उसकी तुलना में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है।

प्र० क्रमांक (15)

(अथवा)

उत्तर : →

म० प्र० विद्वेड़ा वर्ग आयोग : →

म० प्र० विद्वेड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। आयोग में 3 शासकीय सदस्य होंगे।

ये प्रायः ऐसे व्यक्ति होंगे जो पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित मामलों में विशेष अनुभव रखते हों।

आयोग का कार्य : →

- (i) संविधान अथवा सामान्य विधि द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों को दिये गये संरक्षण की दिशा में प्रयास किया जाना।
- (ii) पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए बनें कार्यक्रमों को समुचित तथा प्रथासुमप कार्यक्रमों की निगरानी करना एवं ऐसे कार्यक्रमों को अद्विकार्थिक प्रभावशाली बनाने हेतु सुझाव देना।
- (iii) लोक सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में सुझाव देना।



laser

(iv) सूची में किसी वर्ग को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार करना आयोग इस बारे में भी परामर्श देगा की कौन से वर्ग पिछड़े वर्गों की सूची से निकाल दिये जायें।

क्रीमी लेयर में आने वाले वर्गों का निर्धारण।

प्र० क्रमांक (16)

उत्तर :-> भारत में क्षेत्रवाद के उदय के चार कारण निम्नलिखित हैं :->

(1) क्षेत्रीय विभिन्नता :- क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति विभिन्नता के कारण विकसित होती है। भाषायी आधार राज्यों के गठन के बाद तमाम राज्यों में अनेक ऐसे समूह अस्तित्व में रह गये जो स्वतंत्र राज्य इकाई के आकांक्षी।

(2) भाषायी लगाव :- भाषायी लगाव क्षेत्रवाद का और प्रमुख कारण है।

सन् 1958 में राज्य पुनर्गठन पर विचार करने के लिए दर आयोग की नियुक्ति की गयी थी। इसके बावजूद राजनीतिज्ञों ने अपने निहित स्वार्थों के चलते कि भाषायी हितों को प्रक्षुब्ध नैना जारी रखा।

③ विकसित क्षेत्रों का असन्तुति आर्थिक विकास :-

राज्यों के अलग-अलग भागों में आर्थिक विकास की असन्तुति स्थिति भी क्षेत्रवाद का एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए - असम में हाल असम स्टूडेंट्स द्वारा चलाया गया आन्दोलन इसी भाव से प्रेरित है।

④ निहित राजनीति स्वार्थ :-

क्षेत्रवाद के राजनीतिक कारण भी होते हैं। लूभी-लूभी स्थानीय और क्षेत्रीय राजनेता भी अपनी पृथक् राजनीति पहचान बनाने के लिए इस तरह के आन्दोलनों को प्रेरित हैं।



प्रश्न क्रमांक (17)

उत्तर :-

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं :-

- 1) संविधान और विधियों के अधीन महिलाओं से सम्बन्धित समस्त मामलों का अन्वेषण और परीक्षण करना।
- 2) महिलाओं के प्रति विभेद एवं अत्याचार के मामलों का अन्वेषण करना।
- 3) महिलाओं की दशा सुधारने हेतु उपायों के क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।
- 4) महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास हेतु योजनाओं में सहभागिता तथा सुझाव देना।
- 5) केन्द्र और किसी राज्य के आधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।
- 6) जेल, रिहाउट गृह नारी विकेन्द्र आदि जै रक्षित वाली महिलाओं की स्थिति का अन्वेषण करना तथा इन

B
S
E

Inkjet Printer Label A
AST-15 99



स्थानों का निरीक्षण करना)

7) महिलाओं से सम्बन्धित किसी मामले पर सरकार को रिपोर्ट (Report) देना।

8) किसी अन्य मामले का अन्वेषण करना जो इसे केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपा जाये।

प्र० क्रमांक (18)

(अथवा)

उत्तर :-

भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति निम्नलिखित कार्यों के द्वारा अपनायी गयी है :-

1) विश्व शांति में भूमिका निर्वाह करने की इच्छा :-

भारत ने यह महसूस किया कि वह अमरीकी मा सोवियत खेम में सम्मिलित होकर अन्तर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ाने में सहायक होगा क की अन्तर्राष्ट्रीय शांति को आगे बढ़ाने में।

② अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की इच्छा :->

स्वतंत्रता के बाद भारत न तो एक बड़ी शक्ति था और न ही इतनी बड़ी शक्ति की उसे उम्मीद अर्पित किया जा सके। फिर भारत में एक बड़ी शक्ति बनने की सभी सम्भावनाएँ विहित थीं।

B
S
E

③ अपनी निर्णय की स्वतंत्रता को बरकरार रखने की इच्छा :->

भारत किसी राष्ट्र का अनुकरण करण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने निर्णय की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं चाहता था।

④ दोनो गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने की इच्छा :->

यदि भारत किसी बड़े बड़े में सम्मिलित हो जाता तो माध्यम बड़े बड़े से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता था जबकि गुटनिरपेक्ष रह रक्क वह दोनो गुटों से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर सकता था।

प्र० कर्मांक (19)

उत्तर :-

सांस्कृतिक (SAARC) का पूरा नाम :-
 "South Asian Association for Regional
 Co-operation"

सांस्कृतिक के प्रमुख उद्देश्य
 निम्नलिखित हैं :-

- (i) दक्षिण एशिया के जनमानस के कल्याण को प्रोत्साहन देना तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास करना।
- (ii) दक्षिण एशिया में अर्थिक संवृद्धि, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना।
- (iii) दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा इसे मजबूत बनाना।
- (iv) परस्पर विश्वास समझ तथा एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करना।

प्रश्न क्र.

(5) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, वैज्ञानिक तथा प्रशासकीय क्षेत्रों में सामान्य धित के मुद्दों पर सक्रिय सहयोग करना।

(6) अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना।

प्रश्न क्रमांक (20)

(अथवा)

उत्तर :-

4 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयुब खान व भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य ताशकन्द में वार्ता प्रारम्भ हुई।

अन्ततः (19) जनवरी 1966 को ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर हुए।

ताशकन्द समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं :-



1) दोनों पक्षों ने आपस में उच्चे सम्बन्धों का निर्माण करने पर सहमति प्रदान की।

2) दोनों पक्षों ने यह सहमति व्यक्त की कि 25 फरवरी 1966 के पूर्व जिस स्थिति में वे वही से अपनी सीमाएँ वापस बुला लेंगे।

3) दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर युद्ध रेखा की शर्तों का पालन करेंगे।

4) दोनों पक्ष एक-दूसरे की आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

5) दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार को प्रोत्साहित करने तथा पुनः राजनैतिक सम्बन्धों की स्थापना करने का निर्णय लिया।

6) दोनों पक्ष शरणार्थियों के समस्याओं पर विचार करेंगे।

इसके अतिरिक्त आर्थिक व्यापारिक सांस्कृतिक सम्बन्धों को मधुर बनाने पर सहमति व्यक्त की।



प्रश्न क्र.

प्र० क्रमांक (21)

उत्तर ! →

आधुनिकीकरण की चार विशेषताएँ
निम्नलिखित हैं : →

- ① परम्परागत समाज में एक ही व्यक्ति कई पदों को धारण कर लेता है परन्तु आधुनिक समाज में ऐसी व्यवस्था नहीं होती।
- ② आधुनिक समाज में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अलग-अलग संरचनाओं की व्यवस्था होती है।
- ③ आधुनिक व्यवस्था धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया और तर्कसंगत तरीकों को अपनाती है।
- ④ आधुनिक व्यवस्था में व्यक्ति की निष्ठा का स्वरूप राष्ट्रीय या कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय होता है।
- ⑤ आधुनिक समाज में आम जनमानस की व्यवस्था सक्रिय भूमागत होती है।

B
S
E



6) आधुनिक व्यवस्था में भूमिकाओं का वितरण धर्म तथा गोप्यता के आधार पर होता है।

7) आधुनिक समाज में धर्म जाति आदि परम्परागत आधारों का कोई महत्व नहीं होता है।

प्र० क्रमांक ० (22)

उत्तर ! →

राज्य पुनर्गठन

गठन ! →

राज्यों के 29 दिसम्बर 1953 में भाषायी आधार के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन की घोषणा की गयी।

इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति फ़ाजल अली को बनाया गया।
द्वय कुंजरु तथा के. एम. पणिककर को इस आयोग का सदस्य बनाया गया।



राज्य पुनर्गठन की प्रमुख संस्कृतियां निम्नलिखित हैं! →

- (i) पुनर्गठन में राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च प्राथमिकता।
- (ii) एक भाषा एक राज्य के विचार से असंभव।
- (iii) भाषायी एकता प्रशासकीय कर्मठता में सहायक।
- (iv) पुनर्गठन में भाषायी एकता पर ध्यान दिया जाये।
- (v) केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश के नये राज्यों की स्थापना।
- (vi) मद्रास, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, बंगाल, असम और उड़ीसा का अभाव अस्तित्व।
- (vii) त्रिभुज त्रिपुरा असम से सामिल नहीं।
- (viii) मध्य प्रदेश में मराठी भाषी क्षेत्र और गुजरात से गुजराती भाषी क्षेत्र सामिल।
क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना।



योग पूर्व पृष्ठ

पृष्ठ 23 के अंक

कुल अंक

(XI) जहाँ राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्यों और 36 केन्द्रशासित क्षेत्रों की संसुती की थी वही अधिनियम 14 राज्य और 6 केन्द्रशासित क्षेत्रों की स्थापना हेतु संसुती की गयी।

(XII) संविधान में वर्णित राज्यों का चार पक्षीय वर्गीकरण (A, B, C और D) को समाप्त किया जाये और सभी राज्यों को सामान दर्जा प्रदान किया जाये।

प्र० क्रमांक (23)

(अथवा)

उत्तर →
निर्घोषण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं →

(i) समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य विद्यमान आप तथा सम्पत्ति के असमान वितरण का कम करना या दूर करना।

- ② देश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में वृद्धि करना।
- ③ आप तथा सैलगर के अवसरों में वृद्धि की दिशा में प्रयास करना।
- ④ संतुलित द्वीप-विकास की दिशा में प्रयास करना।
- ⑤ अर्थव्यवस्था को संतुलित बनाना।
- ⑥ लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में प्रयास करना।
- ⑦ जनमानस को अवसर की समानता उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास करना।
- ⑧ सामाजिक उत्थान के लक्ष्यों को पूरा करना।
- ⑨ शान्ति और सुरक्षा की दिशा में प्रयास करना क्योंकि शान्ति एवं सुरक्षा के अभाव में किसी प्रकार का विकास सम्भव नहीं है।



परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे ↓

परीक्षा का विषय : विषय कोड : परीक्षा का माध्यम : परीक्षा का दिनांक

राजनीति विज्ञान : 1 : 3 : 0 : हिन्दी

13 06 2020

स्टीकर तीर के निशान ↓ से मिलाकर लगायें

परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केन्द्र क्रमांक की पुनरा
हा० से० सर्टि० परीक्षा
केन्द्र क्रमांक-322354

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर
 जे.के. श्रीवास्तव

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर

उत्तर पुस्तिका का सरल क्रमांक

120 - 1377976

परीक्षार्थी का रोल नम्बर

2	0	3	2	4	6	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

दो शून्य तीन दो चार दस सात शून्य शून्य

BOARD OF SECONDARY EDUCATION, MADHYA PRADESH, BHOPAL

परीक्षार्थी द्वारा भरा जावे →

मुख्य उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ क्रमांक तक कुल प्राप

सं क्रमांक (24)

उत्तर :-
 क्षेत्रवाद :-
 क्षेत्रवाद वह संकीर्ण मनोवृत्ति है जिससे प्रेरित होकर किसी क्षेत्र विशेष के लोग अपने क्षेत्र विशेष की तुलना में अन्य क्षेत्रों को निम्न समझते हैं।

तथा वह अपनी क्षेत्रवादी मनोवृत्तियों के कारण अपने स्थानीय क्षेत्रवादी प्रवृत्तियों को ही बढ़ावा देते हैं।

अंकों का योग



उत्तर :- \rightarrow क्षेत्रवाद के कारणों को रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं :-

(1) संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा :-

सरकार द्वारा विकास कार्य-क्रमों का निर्माण और क्रियान्वयन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि जिससे संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिला सके। यह बात निर्विवाद है कि अब तक भारत में चलोप गये अधिकांश क्षेत्रीय आन्दोलनों के मूल में असंतुलित आर्थिक विकास ही रहा है।

(2) विशिष्ट जातीय समूहों की रक्षा :-

विशिष्ट जातीय समूहों की संस्कृति और पद्धतियों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार को विशेष उपाय किये जाने चाहिए। इस आशय के प्रावधान वैसे भी संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 में किये गये हैं इन्हें पूर्ण इमादारी से लागू किया जाना चाहिए।

3) पिछड़े क्षेत्रों के विशेष ध्यान :-

यथासम्भव पिछड़े दूर क्षेत्रों पर राज्य को विशेष ध्यान देना चाहिए। ताकि उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। सध सरकार को राज्य सरकारों के पिछड़े दूर क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश देना चाहिए।

4) द्वीपीय आन्दोलनों पर अंकुश :-

क्षेत्रवादी आन्दोलनों की दिसात्मक प्रवृत्ति पर कठोरता से अंकुश लगाना चाहिए। सरकार को मृदु वृद्धिपूर्ण स्वरूप करना चाहिए जो किसी भी प्रकार की द्वीपीय आकांक्षों की प्रति संविधान के दायरे में शक्तिपूर्ण ढंग से सम्भव है।

5) भाषनात्मक दृष्टिकोण का विकास :-

क्षेत्रवादी राजनीति को समाप्त करने का सबसे कारगर उपाय भाषनात्मक दृष्टि में कटुता व द्वेष के स्थान पर समानता और भाषा को बढ़ावा देना चाहिए।

प्र० क्रमांक (25)

उत्तर! →

उपभोक्ता के हितों का संरक्षण ही उपभोक्ता संरक्षण है। उपभोक्ता अंसंगठित होते हैं इसलिए उत्पादक वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा सरकार द्वारा उपभोक्ता के हितों की उपेक्षा की जाती है। जिसे उन्हे हानी उठानी पड़ती है।

उपभोक्ता संरक्षण को प्रभावी बनाने हेतु निम्नांकित सुझाव करना चाहिए! →

① ग्रामीण क्षेत्र में विकसित करना! → उपभोक्ता आन्दोलन को ग्रामीण क्षेत्र में विकसित किया जाना चाहिए। जिसे लेणा भागस्को हो सके और उनका शोषण न हो सके।

② महिलाओं की भागीदारी! → उपभोक्ता आन्दोलन में महिलाओं को सक्रिय किया जाना चाहिए। जिसे वे इसमें सक्रिय सहभागीता मित्रा सके।



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

4 पृष्ठीय

परीक्षार्थी द्वारा भरा जाये ↓

परीक्षा का विषय

विषय कोड

परीक्षा का माध्यम

परीक्षा का दिनांक

13 06 2020

राजनीति विज्ञान

1 3 0

हिन्दी

स्टीकर तीर के निशान ↓ से मिलाकर लगायें

उत्तर पुस्तिका का सरल क्रमांक

120 - 1377977

अंकों में परीक्षार्थी का रोल नम्बर

1	2	0	3	2	4	6	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

शब्दों में

1	दो	शुभ	दी	दो	वार	द्वः	सात	शुभ	शु
---	----	-----	----	----	-----	------	-----	-----	----

परीक्षा का नाम एवं परीक्षा केन्द्र क्रमांक की मुद्रा

हा० से० सर्टि० परीक्षा
केन्द्र क्रमांक-322354

पर्यवेक्षक का नाम एवं हस्ताक्षर

संशोधित विद्वं

केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर

यह उत्तर पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ क्रमांक तक कुल प्राप्त

③ प्रयोशास्त्रोपे खोलना! →

मिलावटी सम्मान की जाँच के लिए स्थान-सम्मान पर प्रयोग शालाए खोलना चाहिए खाद्य वस्तु में मिलावट करने पर रोकथाम की जा सके।

④ विभिन्न संचार माध्यम से जागरूक करना! →

उपभोक्ताओं को विभिन्न संचार माध्यमों जैसे → टेलीविजन रेडियो पत्र पत्रिकाओं आदि के माध्यम से उन्हें जागरूक तथा शिक्षित किया जाना चाहिए।

⑤ दूषित खाद्य सामग्री पर प्रतिबन्ध! →

दूषित खाद्य सामग्री पर रोक लगायी जाये। जिसे उपभोक्ता इन पदार्थों का



उपयोग न कर सके तथा वे स्वास्थ्य रहे ।

इन उपायों से हम उपभोक्ताओं को जागरूक करके उन्हें संरक्षण प्रदान कर सकते हैं ।

प्र० क्रमांक (26)

उत्तर : →

भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन निम्नालिखित है : →

① गुटनिरपेक्षता : →

नैट्रल का मानना था की विश्व शांति के लिए यह आवश्यक है की भारत जैसे उभरते हुए राष्ट्रों को अनुसरण का मनोभाव त्यागकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति को अपनाना चाहिए । तथा उसे किसी शक्ति श्रेणी में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लंघन नहीं करना चाहिए ।

② साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का विरोध :-

सोते तौर पर उपनिवेश का आशय उन नीतियों और तरीकों से लिया जाता है जिनके द्वारा साम्राज्यवादी शक्तियाँ अन्य क्षेत्रों तथा अन्य लोगों पर अपना नियंत्रण स्थापित करती हैं।

उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।

③ रंगभेदभाव का विरोध :-

भारत की विदेश नीति प्रारम्भ से ही मानवमात्र के बन्धुत्व के सिद्धान्त पर आधारित रही है। अन्तरराष्ट्रीय घरातल पर रंगभेदवाद के विरुद्ध आवाज उठाने वाला भारत पहला राष्ट्र रहा है।

④ पंचशील :-

भारत प्रारम्भ से ही शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धान्त का अनुयायी रहा है।

शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व का भारत ने पंचशील के पाँच सिद्धान्तों को स्वीकृति के रूप में मूर्त रूप दिया।



5) सभी राष्ट्रों विशेषकर पड़ोसी
राष्ट्रों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध! →

भारत स्वामी राष्ट्रों की आवश्यकता में
विश्वास नहीं करता है। और अपने
द्विपक्षीय विवादों को परस्पर वार्ता से
हल करने व हेतु कृतसंकल्प है।

6) संयुक्त राष्ट्र में दृढ़ आस्था! →

संयुक्त राष्ट्र ही वह अन्तर्राष्ट्रीय
संगठन है जो विश्व में
शान्ति स्थापित कर सही संज्ञा
। अतः शान्ति प्रिय होने के
कारण भारत का संयुक्त
राष्ट्र में भी दृढ़ आस्था